

ज्ञान तत्व 185,

- (क) सेवाग्राम बैठक में लोकस्वराज्य पर विस्तृत चर्चा ।
- (ख) रामतिर्थ अग्रवाल द्वारा रामानुजगंज ब्लॉक के प्रयोग का समर्थन ।
- (ग) रमण सिंह जी द्वारा सुराज्य की वकालत और मेरा उत्तर ।
- (घ) राजीव भगवन जी द्वारा मुझे समीति में शामिल करने के विषय में स्पष्टिकरण ।
- (च) अपनों से अपनी बात में लोकस्वराज्य के साथ आर्थिक मुद्दे जोड़ने में सतर्कता ।

### (क) सेवाग्राम बैठक

दिनांक उन्नीस, बीस, इक्कीस सितम्बर को सेवाग्राम आश्रम में बंग जी के आमंत्रण पर लोक स्वराज्य संगोष्ठी सम्पन्न हुई जिसमें उन्नीस और बीस तारीख को लोक स्वराज्य पर खुली स्वतंत्र चर्चा हुई तथा इक्कीस तारीख को मैंने अभियान से जुड़े विचार रखे ।

दो दिनों में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई कि वर्तमान समय में आर्थिक समानता को अधिक प्राथमिकता दी जाय या राजनैतिक स्वतंत्रता को पहली प्राथमिकता प्राथमिकता माना जाय। दोनों ही प्रश्नों के गंभीर विद्वानों ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किये। अन्त में निष्कर्ष निकला कि दोनों ही प्राथमिकताओं का महत्व होते हुए भी लोक स्वराज्य अभियान राजनैतिक स्वतंत्रता को महत्व देकर उस दिशा में संघर्ष करता रहेगा। आर्थिक मुद्दों पर संघर्ष के लिये किसी अन्य बैनर का उपयोग किया जा सकता है, किन्तु किसी भी स्थिति में लोक स्वराज्य का लक्ष्य राजनैतिक सत्ता का अकेन्द्रीकरण ही होगा और वह अकेला ही रहेगा। उसमें कोई और मुद्दे लक्ष्य के रूप में शामिल नहीं हो सकते। लक्ष्य प्राप्ति को सशक्त करने के लिये कुछ सहायक मांगे शामिल की जा सकती हैं। जिस तरह वर्तमान में प्रतिनिधि वापसी या राष्ट्रपति के वेतन आदि को जोड़ा गया है। उसका अर्थ हुआ कि यदि प्रशासन से कोई निर्णायक बात होगी तो उसका आधार एकमात्र राजनैतिक सत्ता अकेन्द्रीकरण ही है। अन्य मुद्दों पर तात्कालिक या सहायक चर्चा तो संभव है किन्तु निर्णायक समझौता संभव नहीं।

इस चर्चा में रहस्य खुला कि विनोबा जी भी स्वतंत्रता के पूर्व पूरी तरह स्वराज्य को ही प्राथमिकता दिया करते थे। उन्होंने सन 1942 में इस संबंध में एक पुस्तक भी लिखी। पुस्तक के अंश भी पढ़कर सुनाये गये। प्रश्न उठा कि गाँधी जी के मरने के बाद स्वराज्य की अवधारणा को पीछे करके आर्थिक मुद्दों को आगे लाने का काम किसने किया? स्वतंत्रता के बाद भी लोहिया और जे०पी० तो चौखंभा राज्य, सप्त क्रान्ति या सम्पूर्ण क्रान्ति के नाम से स्वराज्य की आवाज उठाते रहे किन्तु गाँधी के अन्य मानने वालों में इस आवाज को दबाया क्यों? यह बात तो स्पष्ट हुई कि स्वराज्य की दिशा को अन्य दिशाओं में मोड़ा गया। यहाँ तक कि विनोबा जी की लिखी हुई गीता प्रवचन पुस्तक को भी खूब बढ़ाया गया। किन्तु उन्ही की लिखी दूसरी पुस्तक "स्वराज्य शास्त्र" अनेक आल्मारियों में उसी तरह धूल चाटती रही जिस तरह जे०पी० की सन पंचचन की लिखी पुस्तक लोक स्वराज्य लोहिया तो अछूत माने ही जा चुके थे। आज भी जब लोक स्वराज्य की बात उठती है तो कुछ अन्य मुद्दों को अधिक महत्वपूर्ण बताकर लोक स्वराज्य की भूख को भ्रमित करने का प्रयत्न देखा ही जा रहा है। इस मुद्दे पर इस बैठक में विस्तार से चर्चा नहीं हो सकी, क्योंकि समय का अभाव था। अन्त में तय हुआ कि सात लोग बैठकर गाँधी जी की पुस्तक "हिन्द स्वराज्य", विनोबा जी की "स्वराज्य शास्त्र", जयप्रकाश जी की "लोक स्वराज्य" तथा लोहिया जी की "सप्त क्रान्ति" अवधारणा को

मिलाकर विचार मंथन करे तथा मार्ग दर्शन दें। यह कार्य अविनाश भाई काकड़े सेवाग्राम को सौंपा गया। यह भी तय हुआ कि दो-तीन माह में एक शिविर सेवाग्राम में रखा जावे, जिसमें अपने कार्यकर्ताओं को लोक स्वराज्य संबंधी प्रशिक्षण तीन दिन का रखा जावे। स्थान सेवाग्राम हो सकता है। दायित्व अभिषेक अज्ञानी जी भोपाल को दिया गया। वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि से प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम चल रहा है वह दिल्ली कार्यालय के संचालन में यथावत तथा तीव्र गति से चलता रहे। मार्च में दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम रखा जावे, जिसकी व्यवस्था और संचालन ओम प्रकाश जी दुबे करें। एक कार्यक्रम धनवाद के लिये जय किशन जी ने प्रस्तावित किया जिसमें सांसद निधि का विरोध करने की बात तय की गई। इसकी व्यवस्था जय किशन जी करेंगे ही। इस तरह योजना पर सहमति बनी। यह भी तय हुआ कि एक प्रतिनिधि मंडल सोभनाथ जी चटर्जी से जाकर प्रतिनिधि वापसी संबंधी मुद्दे को आगे लाने हेतु चर्चा करें। इसकी योजना जनार्दन भाई जलगांव ने स्वीकार की।

तीसरे दिन मैंने बजरंग मुनि ने समापन भाषण में स्पष्ट किया कि लक्ष्य और मार्ग की धालमेल नहीं करनी हैं। स्वतंत्रता गॉंधी जी का लक्ष्य था और नमक सत्याग्रह सहायक ! हमारा लक्ष्य सत्ता के अधिकारों का अकेन्द्रीकरण हैं। अन्य मुद्दों को प्राथमिक समझने वाले अन्य मंचों का उपयोग करे ! हमारे लोग भी उसका साथ दे सकते हैं किन्तु लोक स्वराज्य अभियान की मुख्य धार को भ्रमित करना ठीक नहीं ! इसी तरह यह भी बताया गया कि आर्थिक असमानता की अपेक्षा राजनैतिक गुलामी अधिक घातक है इस निष्कर्ष से जो लोग विरुद्ध हैं वे लोग कोई अन्य मंच क्यों नहीं खोज लेते ? मैंने दो टूक कहा कि राजनैतिक स्वतंत्रता के सहायक के रूप में आर्थिक असमानता विरोध की चर्चा संभव है किन्तु स्वतंत्र विरोध संभव नहीं। इसलिये न तो हमारे साथी इस संबंध में भ्रम में रहे और ना भ्रम में डालें। मेरे इस कथन के बाद यह बात स्पष्ट हो चुकी थी। इसके बाद बंग जी ने भी अपने समापन भाषण में इच्छा प्रकट की कि अब मुद्दों पर चर्चा बंद करके सिर्फ़ क्रिया पर चर्चा होनी चाहिये और ये चर्चा को कार्य रूप में डाला जाना चाहिये!

मैंने समापन के बाद सोचना शुरू किया कि गॉंधी विनोबा जी की स्वराज्य की अवधारणा धूमिल क्यों और कैसे हुई? गॉंधी विनोबा जयप्रकाश लोहिया आदि सब के सब तो स्वराज्य की अवधारणा के पक्षधर थे! फिर गॉंधी के जाते ही क्या और कैसे उलट गया? स्पष्ट है कि उस समय कम्युनिस्ट भी केन्द्रित सत्ता के पक्षधर थे और संघ भी। नेहरू जी पटेल जी अंबेडकर जी प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रियकरण के समर्थक नहीं थे किन्तु अंदर अंदर तो केन्द्रियकरण चाहते ही थे गॉंधी हत्या में संघ बदनाम होने के बाद कुछ साम्यवादियों ने लुक छिपकर सत्ता में प्रवेश किया तो कुछ ने सर्वोदय में! नेहरू जी ने धीरे धीरे विनोबा जी को कमजोर किया और वामपंथी नेहरूवादी केन्द्रियकरण की नीति मजबूत होती रही और विनोबा जी चुप रहें। लोहिया जी चिल्लाते रहे और जयप्रकाश जी हाथ मलते रहे किन्तु कोई कुछ नहीं कर सका ! पूरी ताकत से लोक स्वराज्य की अवधारणा को या तो दबाया गया या कुचला गया जिससे वह कभी सत्ता के लिये चुनौती न बन सकें। यह नेहरू सोच आज भी जारी हैं। यदि जारी न होती तो आज का सर्वोदय इस तरह सेवाग्राम में बैठकर लोकस्वराज की चर्चा के ही विरुद्ध निर्णय नहीं करता जैसा उसने पिछले दिनों किया। लगता है कि आज भी सर्वोदय का एक छोटा वर्ग इतना शक्तिशाली है कि वह वामपंथियों के प्रभाव में आकर या सत्ता की दलाली में इतना भी नीचे उतर सकता है!

सेवाग्राम में सम्पन्न चर्चा ने स्पष्ट किया कि धीरे धीरे अनेक सर्वोदय कार्यकर्ता खुलकर सामने आते जा रहे हैं आशा की जानी चाहिये कि जल्द ही सर्वोदय एक जूट होकर गाँधी विनोबा जयप्रकाश की स्वराज्य की इच्छा में लगेगा और शीघ्र ही परिणाम दिखने शुरू हो जायेंगे!

(ख) प्रश्न: श्री रामतीर्थ अग्रवाल मनोरोग विज्ञानी हरिनगर दिल्ली

समीक्षा: आपने सरगुजा जिले के रामानुजगंज ब्लॉक के सौ गाँवों में जिस लोक ग्राम सभा का चित्र खींचकर सम्मेलन में बताया वह सिर्फ हवाई बातें न होकर एक धरातल का यथार्थ हैं। ऐसी ग्राम सभाएँ सिर्फ वर्तमान ट्रेडीशनल ग्राम सभाओं को ललकार ही नहीं रही बल्कि वास्तविक समाधान भी प्रस्तुत कर रही हैं।

वर्तमान में ग्राम सभाओं का जो स्वरूप है वह तो संघर्ष का अखाड़ा मात्र है। पंच सरपंच और अधिकारियों के बीच अधिकारों का संघर्ष चलता ही रहता है। दूसरी ओर आदिवासी हरिजन सवर्ण स्त्री पुरुष आदि के बीच भी खींचतान चलती ही रहती है। आपने जो चित्र रखा उसमें ऐसे सभी विवादों से मुक्ति मिलेगी। ये सभाएँ टकराव पैदा न करके दूर करने का आधार बनेगीं।

प्रकाशवीर जी शास्त्री हमेशा कहा करते थे कि व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। यदि उसका चिन्तन तथा उसकी सक्रियता ठीक दिशा में हो तो वह अकेला व्यक्ति भी हजारों को राह दिखा सकता है। आपका यह प्रयास सिर्फ अकेले का प्रयास न होकर हम सबका प्रयास है। आप लोक ग्राम सभा के प्रयत्नों को मजबूती से बढ़ाइये हम सब आपके साथ हैं।

उत्तर: पचपन वर्षों की निरंतर खोज के अनुभव के आधार पर निकले निष्कर्षों के मूर्त रूप देने का समय आ गया। एक ओर तो हम समाज सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत ज्ञानतत्व विस्तार कार्यक्रम शुरू कर ही चुके हैं दूसरी ओर राज्य कमजोरी करण अभियान को भी दो भागों में किया जा रहा है 1 सविधान में परिवार गाँव जिले के अधिकारों की सूची शामिल कराने के लिये राष्ट्र व्यापी जनमत जागरण 2 धर्म जाति क्षेत्र लिंग उम्र के भेदभाव मुक्त ग्राम पंचायतों का एक ब्लॉक में गठन। यह गठन जल्दी ही शुरू हो रहा है। मैंने दिल्ली में इस संबंध में बताया भी था। जब तक हम बिल्कुल गाँव स्तर से जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, उम्र, गरीब अमीर के भेदभाव मूलक सरकारी कानूनों से मुक्त व्यवस्था तैयार नहीं करते तब तक समाज टूटता ही रहेगा।

आज ही हमारे एक साथी ने हिन्दी के साथ हो रहे भेदभाव के प्रति कुछ करने की बात कही है। कई साथी महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव की बात करते हैं तो कई हिन्दुओं के साथ या आदिवासी हरिजनों के साथ। यदि अपने साथियों के उक्त विचारों पर हम विचार करें तो इन भेदभाव में सच्चाई भी दिखती है। मैं ऐसे भेदभाव मूलक व्यवहारों से इन्कार नहीं

करता किंतु मैं समझता हूँ कि इन सब प्रकार के भेदभाव से भी अधिक घातक भेदभाव है शराफत के विरुद्ध धूर्त अपराधी तत्वों का सशक्तिकरण।

मेरे विचार में पहले शराफत की सुरक्षा की सक्रियता आवश्यक हैं। उसके बाद हम अन्य सक्रियताओं पर बढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अन्य सभी भेदभाव दूर करने के प्रयत्न इस शराफत सशक्तिकरण अभियान में बाधक है, साधक नहीं। फिर भी यदि कोई साथी वह काम कर रहे है तो मैं उनका विरोध नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूँ कि आप मुझे इस राह चलने मत भटकाइये। अभी उन्नीस बीस सितम्बर को सेवाग्राम में अर्थिक असमानता को गुलामी तथा अपराधीकरण से भी अधिक खतरनाक बताने वाले साथियों से दो टुक शब्दों में कहा गया कि आप अपनी राह चलने को स्वतंत्र हैं किंतु आप भविष्य में लोकस्वराज्य की बैठकों में आवें तो लोक स्वराज के अतिरिक्त के अपने ऐजेन्डे को बाहर रख कर आइये अन्यथा मत आइये। हमें आपकी सर्वोत्तम सलाह नहीं चाहिये। हमें चाहिये आप से लोकस्वराज पर सलाह। हमें आप से चाहिये भेदभाव मुक्त ग्राम सभा के गठन की योजना। आप सलाह दे रहे हैं भेदभाव मूलक आर्थिक विषमता दूर करने की योजना जो मुझे जरूरत नहीं। मैंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि हम वर्ग संघर्ष की जगह गाँवों में वर्ग समन्वय की योजना पर काम करने जा रहे हैं। आपका वर्ग संघर्ष चाहे कितना भी न्याय संगत क्यों ना हो किंतु हमारी लोक ग्राम सभा के वर्ग समन्वय में वह घातक होने से वर्तमान में हमारे लिये जहर के समान ही हैं। हमारे कुछ साथियों को यह बात बुरी भी लगी और कई साथियों ने तो साथ छोड़ने तक की धमकी भी दी तो हमने उनकी नाराजगी को मान लिया और कह दिया कि हमारा लोक ग्राम सभा का गठन वर्ग समन्वय को ही आधार रखकर होगा आप साथ रहे या न रहे यह आप पर निर्भर है।

मेरा आप से निवेदन है कि हम जिस राह पर चल रहे हैं उसके प्रति आपने समर्थन व्यक्त किया इससे हमें सम्बल मिला। प्रकाशवीर जी शास्त्री पूर्व में ही हमारे मार्ग दर्शक रहे हैं और अब उनके विचार हमारा सम्बल बने रहेंगे।

(ग) प्रश्न – छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री डारमण सिंह के आप प्रशंसक हैं उन्होंने रायपुर की पत्रकार वार्ता में बताया है कि गाँधी जी स्वावलम्बी गाँव बनाकर तब ग्राम स्वराज लाना चाहते थे उनके अनुसार गाँधी जी सुशासन पहले चाहते थे जिससे सुशासन को स्वशासन की दिशा में बढ़ाया जा सके। रमण सिंह जी ने कहा है कि गाँधी जी आजादी को पहले सुराज में और बाद में स्वराज्य में बदलना चाहते थे। इस संबंध में आपके विचार क्या हैं?

उत्तर.. मुझे तो आज तक पता नहीं कि गाँधी जी ने कभी सुराज के बाद स्वराज्य की बात कही ही। यह बात तो गाँधी जी के जाने के बाद नेहरु जी सर्वोदय नेतृत्व या अन्य जीवित गाँधी ही कहते रहे। महात्मा गाँधी ने ऐसा कभी नहीं कहा। रमण सिंह जी ने जो कहा है वह पूरी तरह असत्य भी है और गलत भी। असत्य तो इसलिए कि गाँधी जी ने ऐसा नहीं कहा था और गलत इसलिए कि सुराज्य स्वराज्य का परिणाम होता है आधार नहीं। इसका अर्थ हुआ कि पहले स्वराज्य आयेगा और तब उसके परिणाम स्वरूप सुराज आयेगा।

पिछले साठ वर्षों से स्वराज्य के बिना सुराज की बात करने वाले देख रहे हैं कि सुराज नहीं आया क्योंकि स्वराज्य के बिना सुराज का प्रयत्न हुआ। यह असंभव तथा प्रकृति विरुद्ध प्रयत्न होने से असफल हुआ। रमणसिंह जी ने एक बात अवश्य कही है कि सुराज तो आ ही रहा है किन्तु अब स्वराज्य आना चाहिये। वे मुख्य मंत्री हैं। उनकी नजर में सुराज आ गया चाहे आया या नहीं, यह हमारे लिये बहस का विषय नहीं। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि रमण जी स्वराज्य की दिशा में एक कदम उठाएँ। वे चाहें तो स्वराज्य की दिशा में एक कदम उठाते हुए निम्न घोषणाएँ कर सकते हैं।

1. छत्तीसगढ़ का किसान अपना उत्पादन देश के किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति को किसी भी भाव पर बेचने के लिये स्वतंत्र है। मैं आप को बता दूँ कि छत्तीसगढ़ का किसान अपना गन्ना सरकारी मूल्य पर सरकार को ही देने हेतु वाध्य है यदि वह सरकारी चीनी मिल के पच्चीस किलोमीटर के अन्दर गन्ना उत्पादन करता है। किसान गुड नहीं बना सकता ।

2. छत्तीसगढ़ का कोई भी निवासी अपनी जमीन देश के किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बेचने के लिये स्वतंत्र है। विदित हो कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को अपनी जमीन गैर आदिवासियों को बेचने पर प्रतिबंध है। पैसा है छत्तीसगढ़ के बाहर के गैर आदिवासियों के पास और जमीन है आदिवासियों के पास । गैर आदिवासी की जमीन की कीमत यदि एक करोड़ है तो आदिवासी की एक लाख भी नहीं है क्योंकि आदिवासी पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन तो रख सकता है किन्तु पैसा नहीं। पैसा रखने का अधिकार सिर्फ सवर्णों के पास सुरक्षित है ।

3. छत्तीसगढ़ में कृषियोग्य भूमि में खरीदने के दस वर्ष तक कोई उद्योग नहीं लगाया जा सकता क्योंकि छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि घट जाने का खतरा है। इसका अर्थ यह हुआ कि दिल्ली हरियाणा पंजाब के लोग कृषि भूमि में उद्योग लगा सकते हैं किन्तु छत्तीसगढ़ के लोग कृषि भूमि में उद्योग नहीं लगा सकते । गैर आदिवासी भी अपनी जमीन ऐसे गैर आदिवासी को नहीं बेच सकता जो कोई मकान बनाना चाहे या छोटा मोटा भी उद्योग लगाना चाहे ।

4. छत्तीसगढ़ का किसान अपने निज भूमि पर लगे पेड़ नहीं काट सकता क्योंकि छत्तीसगढ़ का पेड़ कटने से हरियाणा पंजाब दिल्ली के पर्यावरण को नुकसान होगा ।

ऐसे अनेक कानून हैं जो शहरी सवर्णों को सशक्त करने के लिये छत्तीसगढ़ की रमण सिंह सरकार में आज तक इस तरह चल रहे हैं जैसे छत्तीसगढ़ दिल्ली हरियाणा की सम्पन्न भैसो का चरागाह हैं। इसे एक पिछड़े क्षेत्र के रूप में ही रहना चाहिये क्योंकि यही इनकी संस्कृति हैं और यही सम्पन्नों शहरो की आवश्यकता छत्तीसगढ़ के लोग जमीनें मनमाने बेचकर बराबरी में ना आ जावें, गन्ने का मनमाना गुड ना बना लें, पेड़ न काट दें या कोई उद्योग ना खोल लें इसके लिये उनकी संस्कृति को बचाने के नाम पर उनके पुराने स्वाभिमान की याद दिलाते रहना आवश्यक मानकर योजनाएँ बन रही हैं ।

मेरा रमण सिंह जी से निवेदन है कि वे छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति सुरक्षा के नाम पर पिछड़े नमूने के रूप में अविकसित बनाये रखने के षडयंत्र से सावधान रहें तभी स्वराज आ सकेगा और इसकी पहली किशत के रूप में वर्ग संघर्ष को वर्ग समन्वय में बदलने की पहल छत्तीसगढ़ से हो तो अच्छा होगा ।

प्रश्न उठता है कि ऐसी छूट होते ही आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी खरीदकर उन्हें भूमिहीन बना देंगे। यह बात सच भी है किन्तु आदिवासी जमीन रखे और बाकी लोग महल बनावें यह कितना उचित है? ग्राम सभा को पावर दीजिये कि वह निर्णय करें। सरकार अपने कानून हटा लें। यदि ग्राम सभा को पूँजीपति ढग लेंगे तब क्या होगा? मेरा प्रश्न है कि आदिवासी या ग्राम सभा ना समझ है और राज्य से जुड़े लोग धुर्त है या उनकी नीयत खराब है तो हम खराब नीयत वाले के साथ रहे या ना समझों के साथ। ग्राम सभा धेखा खा सकती है किन्तु दे नहीं सकती। राज्य से जुड़े लोग धेखा दे सकते हे किन्तु धेखा खा नहीं सकते ।

स्वतंत्रता के बाद गाँव गरीब श्रमजीवी ने धोखा खाया है और राजनीति से सम्बन्धितो ने दिया है। हर नेता कहता है कि आदिवासी ग्रामीण ठगा जायेगा । उसे बचाने के लिये सरकार हैं। यह गन्ने की सरकारी खरीद बाध्यता उसे बचाने के लिये किस तरह है यह आज तक समझ में नहीं आया। इसलिये मेरा सुझाव है कि नीयत खराब वालो की अपेक्षा ना समझी अधिक विश्वसनीय होगी । यह गंभीर विषय है । इस पर और चर्चा चलेगी । किन्तु कृषि उपज विक्रय तो साफ विषय है। रमण सिंह वहीं से शुरूआत करें। खेती की जमीन में उद्योग लगाने पर रोक षडयंत्र है। इसमें तो पहल कर सकते हैं। अपने पेड़ काटने की छूट में तो विवाद नहीं है। कम से कम यहीं से शुरू हो ।

## (घ) स्पष्टीकरण

मुझे पता चला है कि श्री राजीव भगवान जी ने अपने आंदोलन के नेतृत्व की सूची प्रकाशित की है। उस सूची में प्रवीणा देसाई, विजय कौशल जी महाराज, मधुकान्ता बेन, शरद साधक जी, राजेन्द्र जी जोशी, सीता रमैया जी, देवेन्द्र स्वरूप जी अग्रवाल तथा सुनीता जैन के साथ साथ मेरा भी नाम प्रकाशित किया है। मैंने पच्चीस दिसम्बर दो हजार आठ को ही स्वयं को ट्रस्ट को समर्पित कर दिया है। इसलिये मेरे लिये ऐसे किसी कार्यक्रम के नेतृत्व की टीम में शामिल होना संभव नहीं है। यह बात राजीव जी को मैंने बता भी दी थी। मैं पुनः स्पष्ट कर दूँ कि ऐसे किसी भी आयोजन के आयोजक या नेतृत्व में मेरी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। आवश्यकता नुसार आमन्त्रित के रूप तक ही मेरी भूमिका समझी जानी चाहिये।

## (च) अपनो से अपनी बात

पच्चीस दिसम्बर के बाद उन्तीस तीस अगस्त को दिल्ली में मैंने अपनी पहल पर बैठक की थी। दिसम्बर के बाद आठ माह मे मैंने अनुभव किया कि आर्थिक असमानता को प्राथमिकता देने का भूत लोक स्वराज की अवधारणा को स्पष्ट करने में बाधक हो रहा है। मुझे दिल्ली रहते हुए भी आचार्य पंकज जी द्वारा बार बार ऐसी दिशा दी जाती रही और मेरे अस्वीकार के बाद उन्होंने वात्सल्य जी के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन मंच नाम से एक नया संगठन जून दो हजार आठ में बना लिया था तथा हरिद्वार रहने लगे थे। इस दिल्ली बैठक में भी यह मुद्दा कहीं न कहीं उठने के बाद मैंने दो टूक स्पष्ट किया है कि हमारा संघर्ष का एक ही मुद्दा है लोक स्वराज जिसका अर्थ है शासन मुक्ति की दिशा। इस संघर्ष में कोई आर्थिक मुद्दा शामिल नहीं है अन्य आर्थिक या समाजिक मुद्दों को हम सहायक के रूप में जोड़ सकते हैं किन्तु संघर्ष का मुद्दा एक ही रहेगा। मेरे इस कठोर स्पष्टीकरण के बाद बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि जो साथी आर्थिक असमानता को पहला मुद्दा मानते हैं या लोक स्वराज के साथ जोड़ना चाहते हैं वे अलग से काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। बात यहाँ तक आई कि अपने निकटस्थ साथी आचार्य पंकज जी शुद्ध होकर बीच में ही बहिष्कार करके हरिद्वार चले गये और मेरे साथ पूर्ण संबंध विच्छेद का पत्र लिख दिये।

सेवाग्राम आश्रम में बंग जी ने जो बैठक बुलाई थी उसमें भी आर्थिक और लोक स्वराज के बीच प्राथमिकता के लिए रस्सा कसी चलती रही। रोशन लाल जी ने बहुत जोरदार ढंग से अपना पक्ष रखा। अन्त में वहाँ भी मैंने दो टूक स्पष्ट किया कि हमारे आंदोलन का एक सुत्री लक्ष्य है लोक स्वराज। इसमें कोई आर्थिक समाजिक मुद्दे शामिल नहीं है। परिवार गाँव जिले को निर्णय की अधिकतम स्वतंत्रता हो इसकी सीमाएँ तय करके वे सीमाएँ संविधान में सूचीबद्ध की जानी चाहिये। जो लोग इस संघर्ष से हटकर आर्थिक समाजिक मुद्दों को जोड़ना चाहते हैं वे भिन्न बैनर तले स्वतंत्रता पूर्वक वह कार्य कर सकते हैं। लोक स्वराज अभियान की मांग सिर्फ एक ही है हमने सांसदों से चार प्रश्नों पर वार्तालाप तय किया उसका अर्थ यह नहीं कि ये चार हमारी मांगें हैं इन चार या ऐसी अन्य मांगों को जोड़कर हम अपने संघर्ष को तेज कर रहे हैं जैसे गाँधी जी ने भी स्वतंत्रता के साथ नमक आंदोलन को जोड़ा था किन्तु मांग हमारी एक सुत्रीय ही है। हमने वेतन भत्तों की मांग उठाई। राष्ट्रपति से मिले। जन्तर मन्तर पर प्रदर्शन किया। देश भर में जनप्रतिनिधियों तक विभिन्न माध्यमों से अपनी बात पहुँचाई। सरकार ने पहल करके वेतन भत्ते रोकने की शुरुआत की है यह हमारी मात्र इतनी ही सफलता है कि हमारे तर्कों में दम है किन्तु हमारी यह सफलता दूर दूर तक लोक स्वराज में सहायक नहीं है क्योंकि सत्ता अपने अधिकार कम करने की दिशा में जरा भी नहीं सोच रही। इसलिये मैं सतर्क करना चाहता हूँ कि लोक स्वराज्य के साथ गाँधी के जाते ही छल शुरु हो गया था जो साठ वर्षों से जारी है। वैसा अब भी हो सकता है जब आकर्षक नारे लोक स्वराज्य की

अवधारणा को ही दूर बिठाकर आर्थिक सामाजिक संघर्ष को आगे ले आवें और हम फिर ठगे जावें । चिंता साथियों की नहीं है । चिंता सिर्फ यही है कि हम ठगे न जावें ।

हमारे दिल्ली कार्यालय ने ज्ञान तत्व में उन स्थितियों का उल्लेख किया है कि विनोबा जी ने सन बयालीस में स्वराज्य शास्त्र लिखा जय प्रकाश जी ने लोक स्वराज्य लिखा लोहिया जी ने सप्त कान्ति की आवाज उठाई गाँधी जी तो मरते तक ग्राम स्वराज्य की ही बात करते रहें । किन्तु गाँधी के जाते ही सत्ता और सर्वोदय नेतृत्व ने मिलकर स्वराज्य की अवधारणा को न केवल छोड़ दिया बल्कि ग्राम स्वराज्य शब्द का अर्थ ही बदल दिया क्योंकि साम्यवादी संस्कार मजबूती से हावी हो चुके थे । सुराज्य का आकर्षक नारा और चेहरा हमारे अच्छे अच्छे चरित्रवानो को भ्रमित कर गया । अब सुशासन और स्वशासन की स्पष्ट अवधारणा के बीच हम भ्रमित बिल्कुल न हो हम स्वशासन के लिये संघर्ष करेंगे उसके साथ साथ विभिन्न मंचो के माध्यम से हम सुशासन की आवाज भी उठाते रहेंगे किंतु यह सुशासन की आवाज स्वशासन की आवाज को मजबूत करने के लिए ही होगी ,धोखा देकर किनारे करने के लिए नहीं यह ध्यान रखना है

सेवाग्राम मे तथा दिल्ली में बैठकर कुछ योजनाएँ बनी है उनमें आप अधिक से अधिक लगे । कुछ साथी अलग हुए यह कोई निराशा की बात नहीं । लक्ष्य स्पष्ट होना ही चाहिये दिल्ली उन्तीस तीस की बैठक ने लक्ष्य साफ किया और सेवाग्राम बैठक ने उसकी पुष्टि की यह हमारी ठीक दिशा को रेखांकित करती है आप भविष्य में भी सावधन रहे यही आपसे अपेक्षा है ।







